

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनागत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 604]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2007—पौष 1, शक 1929

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2007

क्र. एक. 10-29-06-पचास-2.— बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 36 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2007 है.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएँ.— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4);

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 17 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग;

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, आयोग का अध्यक्ष;

(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, आयोग का सदस्य;

(ङ) "सचिव" से अभिप्रेत है, आयोग का सचिव;

(च) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(छ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ज) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं की गई हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं.

3. **चयन समिति.**—धारा 18 के परन्तुक में निर्दिष्ट चयन समिति का अध्यक्ष, महिला एवं बाल विकास विभाग का भारसाधक मंत्री होगा.

4. **अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता.**—कोई व्यक्ति, जिसका मानव अधिकार या बाल अधिकारों के अतिक्रमण का पूर्ववृत्त रहा हो, आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

5. **सचिव.**—राज्य सरकार, धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आयोग का सचिव नियुक्त करेगी.

6. **सचिव की शक्तियाँ और कर्तव्य.**—सचिव,—

(एक) को धारा 13 तथा 14 में यथाउपबंधित आयोग की शक्तियाँ और कृत्यों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से आयोग द्वारा किए गए समस्त विनिश्चयों का निष्पादन करने की शक्तियाँ होंगी.

(दो) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसी कि आयोग के कार्यकलापों के समुचित प्रशासन के लिए और धारा 13 तथा 14 में यथाविनिर्दिष्ट इसके दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए अपेक्षित हों.

(तीन) अध्यक्ष के परामर्श से आयोग का सम्मेलन का आहूत करेगा और समस्त संबंधितों को सम्मेलनों की सूचनाओं की तामील करेगा.

(चार) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि सम्मेलन आहूत करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति है.

(पांच) अध्यक्ष के परामर्श से आयोग के प्रत्येक सम्मेलन की कार्यसूची तथा स्वतः स्पष्टीकारक टीप तैयार करेगा.

(छह) कार्यसूची भदों में आने वाले विनिर्दिष्ट अधिलेखों को, आयोग को संदर्भ के लिए उपलब्ध कराएगा.

(सप्त) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यसूची के क्रमजपत्र, सिवाय उन मामलों में जब तुरंत ध्यान दिया जाना अपेक्षित हो, कम से कम सम्मेलन से अग्रिम दो पूर्ण कार्य-दिवसों में सदस्यों को परिचालित हो गए हों.

(आठ) आयोग के सम्मेलनों के कार्यवृत्त तैयार करेगा तथा सम्मेलन में लिए गए आयोग के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा और इसके पश्चातवर्ती सम्मेलन में आयोग के समक्ष आयोग के विनिश्चयों पर की गई कार्रवाई के टिप्पण को रखा जाना भी सुनिश्चित करेगा.

(नौ) यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग की प्रक्रिया उसके कारबार के संबन्धित में उसके द्वारा अनुसरित की गई है.

(दस) अनुदान देने, पदों के सृजन, वेतनमान का पुनरीक्षण, यानों का उपापन, कर्मचारिवृद्ध की नियुक्ति, राज्य विधान सभा में वार्षिक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को रखवाने, निधियों का पुनर्विनियोग, आवासीय स्थान प्रतिनियुक्ति के लिए आयोग के किसी अधिकारी को अनुज्ञात करने और राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु अपेक्षा करने वाले किसी अन्य विषय के संबंध में, महिला एवं बाल विकास विभाग से ऐसे समस्त विषयों पर विचार करेगा.

(ग्यारह) ऐसी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित की गई हैं:

परन्तु ऐंसा कोई भी व्यय, जो किसी एक मद में उसके वित्तीय शक्ति से अधिक हो, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उपगत नहीं करेगा.

(बारह) आयोग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकारी होगा.

7. अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि.—(1) अध्यक्ष, जब तक कि उसे अधिनियम की धारा 7 के अधीन उसके पद से हटा नहीं दिया जाता, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पदधारण करेगा.

(2) प्रत्येक सदस्य, जब तक कि उसे धारा 7 के अधीन पद से हटा नहीं दिया जाता, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि या साठ वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पदधारण करेगा.

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) में अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई व्यक्ति, जो अध्यक्ष का पदधारण करता है, पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा; और

(ख) कोई व्यक्ति, जो सदस्य का पदधारण करता है, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन या अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशन के लिये पात्र होगा:

परन्तु कोई व्यक्ति, जो दो अवधि के लिए अध्यक्ष या सदस्य, किसी भी हैसियत में रह चुका है. यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन के लिये पात्र नहीं होगा.

(4) यदि अध्यक्ष, बीमारी या अन्य किसी अक्षमता के कारण, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है, तो राज्य सरकार, किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण करने या उसकी पदावधि के शेष भाग तक अध्यक्ष का पद धारण करेगा.

(5) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्य सरकार को संनोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा.

(6) मृत्यु, पद त्याग या किसी अन्य कारण से हुई कोई रिक्ति, ऐसी रिक्ति होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी.

8. अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें.—अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें, जिनके लिये इन नियमों में उपबंध नहीं किया गया है, ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएँ.

9. आयोग के कृत्य.—आयोग निम्नलिखित समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) बाल अधिकारों के संरक्षण के लिये तुरन्त प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का परीक्षण तथा पुनर्विलोकन करना तथा उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियाचयन के लिए उपायों की अनुसंसा करना.

(ख) प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य अंतरालों पर, जैसा आयोग ठीक समझे, राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट देना.

(ग) बाल अधिकारों के अतिक्रमण का अन्वेषण करना और ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही शुरू करने की अनुसंसा करना.

(घ) आतंकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, भूतलु हिंसा, एच.आई. वी/एड्स, दुर्व्योहार, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना तथा शोषण, अश्लील चित्रण, तथा वेश्यावृत्ति द्वारा बालकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले समस्त कारणों का परीक्षण करना और ऐसे मामलों में समुचित उपचारात्मक उपायों की अनुसंसा करना.

(ङ) विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, जिनमें कठिन परिस्थितियों में बालक, उपेक्षित और प्रतिकूल परिस्थितियों में बालक, अपभारी बालक, किशोर, परिवार रहित/निराश्रित बालक तथा बंदियों के बालक सम्मिलित हैं, से संबंधित मामलों को देखना तथा समुचित उपचारात्मक उपायों की अनुसंसा करना.

- (च) बाल अधिकारों के बारे में संधियों (ट्रीटीज) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विलेखों का अध्ययन करना तथा विद्यमान नीतियों, कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों का सामयिक पुनर्विलोकन करना तथा बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा करना.
- (छ) बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना तथा उसे बढ़ावा देना.
- (ज) समाज के विभिन्न वर्गों में बाल अधिकारों की जानकारी को प्रसारित करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमीनार तथा अन्य उपलब्ध स्रोतों के माध्यम से इन अधिकारों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना.
- (झ) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी भी किशोर बंदीगृह या बालकों के निवास का कोई अन्य स्थान या ऐसी संस्था जो बालकों के लिये बनी हो, जिसमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित कोई ऐसी संस्था सम्मिलित है, जहां बच्चों को अभिरक्षा या इलाज, सुधार या संरक्षण के प्रयोजन के लिये रखा जाता हो, का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना तथा यदि आवश्यक पाया जाए, तो ऐसी उपचारात्मक कार्रवाई के लिये उन प्राधिकारियों तक ले जाना.

(ञ) निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना:—

- (1) बाल अधिकारों का वंचन या अतिक्रमण;
- (2) बालकों की रक्षा और उनके विकास के लिए उपबंधित विधियों का अक्रियान्वयन;
- (3) बालकों का कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा ऐसे बालकों को अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नैतिक विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुपालन, या ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को सपुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना; और
- (4) किसी ऐसे मामले के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना.

10. आयोग के अतिरिक्त कृत्य.—आयोग, नियम 9 के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का भी निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

- (क) बाल अधिकार पर अभिसमय के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए विद्यमान विधि नीति और प्रथा का विश्लेषण करना बालकों को प्रभावित करने वाली नीति या प्रथा के किसी पहलु के संबंध में जांच करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित नए विधान पर टिप्पणी करना.
- (ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों के कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष और ऐसे अनुरातों पर, जैसा आयोग ठीक समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना.
- (ग) वहां औपचारिक अन्वेषण करना जहां चिन्ता या तो स्वयं बालकों द्वारा या उनकी ओर से संबंधित व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त की गई है.
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि आयोग का कार्य बालकों के दृष्टिकोण से सोपे सूचित किया जाता है जिससे उनकी प्राथमिकताओं तथा परिप्रेक्ष्यों को परिलक्षित किया जा सके.
- (ङ) अपने कार्य में तथा बालक से संबंधित समस्त सरकारी विभागों तथा संगठनों के कार्य में बालकों के दृष्टिकोण को प्रोन्नत करना, उनका आदर करना तथा उन पर गंभीर खिंचार करना.

- (च) बाल अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना तथा उसका प्रचार करना।
- (छ) बालकों के संबंध में आंकड़े संकलित करना तथा उनका विश्लेषण करना; और
- (ज) विद्यालय के पाठ्यक्रम अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा बालकों से संबंधित कार्मिकों के प्रशिक्षण में बाल अधिकारों के समावेशन को प्रोन्नत करना।

11. राज्य आयोग का मुख्यालय.—राज्य आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा।

12. सम्मिलनों का स्थान.—राज्य आयोग, सामान्यतया भोपाल स्थित अपने कार्यालय में सम्मिलन करेगा, किन्तु स्वविवेकानुसार मध्यप्रदेश के किसी अन्य स्थान पर अपना सम्मिलन कर सकेगा, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे।

13. सम्मिलनों की नियतकालिकता.—आयोग, भोपाल स्थित अपने कार्यालय में ऐसे समय पर, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे, नियमित रूप से सम्मिलन करेगा, किन्तु उसके अंतिम सम्मिलन तथा आगामी सम्मिलन के बीच तीन मास का अंतराल नहीं होगा। यद्यपि, अध्यक्ष किसी आवश्यक विनिर्दिष्ट मामले पर विचार करने के लिये उसकी स्वप्रेरणा पर या एक या एक से अधिक सदस्य की प्रेरणा पर, आयोग का विशेष सम्मिलन बुलाए जाने के लिए निर्देश दे सकेगा।

14. परिवारों को निपटाने के लिये प्रक्रिया.—(1) समस्त परिवार, जो राज्य आयोग द्वारा किसी भी रीति में प्राप्त किए गए हों, रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और उन्हें एक क्रमांक दिया जाएगा तथा इस प्रयोजन के लिए गठित दो उदस्यीय न्यायपीठ (बेंच) के समक्ष साधारणतया उसकी प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह से अनधिक के लिए स्वीकृत हेतु रखा जाएगा। साधारणतया निम्नलिखित प्रकृति के परिवार आयोग के लिये ग्राह्य नहीं हैं.—

- (क) ऐसी घटनाओं के संबंध में, जो परिवार प्रस्तुत करने के एक वर्ष से अधिक पूर्व घटित हुई हैं;
- (ख) ऐसे मामलों के संबंध में जो न्यायाधीन हैं;
- (ग) जो स्पष्ट नहीं हैं, बिना किसी नाम से या उद्दम नाम से हैं;
- (घ) जो तुच्छ प्रकृति के हैं;
- (ङ) जो आयोग के अधिकारिता के बाहर हैं।

(2) परिवारों के लिए कोई फीस देय नहीं होगी।

(3) प्रत्येक परिवार हिन्दी या अंग्रेजी में किया जाना चाहिए जिससे कि आयोग तुरंत कार्यवाही करने हेतु समर्थ होगा तथा ऐसा प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए कि उस मामले की प्रकृति पूर्णतया स्पष्ट हो जाए, जिसके कारण परिवार किया गया है। तथापि परिवारों को सुविधानुसार फाइल करने के लिए आयोग, संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में किए गए परिवारों को स्वीकार कर सकेगा। आयोग को, यह स्वतंत्रता होगी कि वह जब कभी आवश्यक समझे अधिकतमों के समर्थन में और जानकारी तथ्य-पत्र फाइल किए जाने की अपेक्षा करे।

(4) आयोग, स्वविवेकानुसार, तार, या ई-मेल से भेजे गए परिवारों और फैक्स के माध्यम से परिवारों को ग्रहण करेगा।

(5) आयोग को किसी परिवार को आरंभ में ही खारिज करने की शक्ति होगी।

(6) किसी परिवार के ग्रहण कर लिए जाने के पश्चात्, अध्यक्ष/आयोग यह निर्देश देगा कि क्या मामले आयोग को जांच के लिए रखा जाए या और अन्वेषण किया जाना चाहिए।

(7) प्रत्येक परिवार के संबंध में, जिस पर अध्यक्ष/आयोग द्वारा कोई ऐसा विनिश्चय किया गया है कि क्या उसकी जांच या अन्वेषण किया जाना चाहिए, तो आयोग संबंधित सरकार/प्राधिकारी से रिपोर्ट/टिप्पणी मंगाएगा और इस प्रयोजन के लिए सरकार/प्राधिकारी को समुचित समय दिया जाएगा।

(8) संबंधित प्राधिकारी की टिप्पणी प्राप्त होने पर, उस मामले के गुणगुण के आधार पर एक विस्तृत टीप आयोग के विचारण के लिये तैयार की जाएगी।

(9) आयोग स्वप्रेरणा से कार्रवाई करेगा.—आयोग स्वविवेकानुसार याचिकाकर्ता को या याचिकाकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, और यदि आयोग की यह राय हो कि ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसके समक्ष मामले के समुचित निपटारे के लिए सुना जाना चाहिए, तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकेगा और जहां आवश्यक हो उसके संबंध में अभिलेख मंगा सकेगा तथा विषयों का परीक्षण कर सकेगा। आयोग उन व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा जिनका चरित्र उसकी जांच की विषयवस्तु है और उसकी राय में उनकी ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और परिवार के समर्थन में साक्षियों के प्रतिपरीक्षण, यदि कोई हो, करने का तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

(10) जहां आयोग के दल (टीम) द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्वेषण किया गया है, वहां उसके पूर्ण होने की तारीख से एक सप्ताह या ऐसे और समय के भीतर, जैसा कि आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाए, ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। किसी द्वािशिष्ट मामले में, यदि आयोग, की यह राय है कि अन्वेषण उचित रूप से नहीं किया गया है या सत्य को सुनिश्चित करने के लिए या उस विषय को उचित रूप से निपटाने में समर्थ होने के लिए उस विषय में और अन्वेषण किया जाना अपेक्षित है तो आयोग स्वविवेकानुसार और अन्वेषण करने के लिये निर्देश दे सकेगा।

(11) आयोग या जब अध्यक्ष द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो आयोग के सदस्यों में से कोई सदस्य स्थल पर जाकर अध्ययन करने के लिए दौरा कर सकेगा तथा जहां किसी एक या अधिक सदस्यों द्वारा ऐसा अध्ययन किया जाता है, तो वह रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र, आयोग को दी जाएगी।

(15) आयोग के कारबार के संव्यवहार के लिये प्रक्रिया.—(1) आयोग का सचिव ऐसे अधिकारियों के साथ, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे, आयोग के सम्मिलनों में उपस्थित होगा।

(2) सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से आयोग के प्रत्येक सम्मिलन के लिए कार्य सूची (एजेण्डा) तैयार करेगा तथा आयोग के उपयोग के लिए टिप्पण तैयार करेगा तथा ऐसे टिप्पण यथासंभव स्वतः स्पष्ट होंगे।

(3) कार्यसूची की मदों में आने वाले अभिलेख आयोग को निर्देश के लिये तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे।

(4) कार्यसूची की कागजपत्र सामान्यतः सम्मिलन के कम से कम दो स्पष्ट कार्यदिवस के पूर्व अग्रिम में सदस्यों को परिचालित कराए जाएंगे। सिवाय ऐसे मामलों में जब आवश्यक ध्यान अपेक्षित हो।

(5) आयोग के प्रत्येक सम्मिलन में चार सदस्यों से, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, गणपूर्ति होगी।

(6) आयोग के समस्त विनिश्चय उसके सम्मिलनों में बहुमत से लिए जाएंगे:

परन्तु मतों की समानता की दशा में, अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

(7) यदि किसी कारण से अध्यक्ष, आयोग के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया कोई सदस्य अध्यक्षता करेगा।

16. सम्मिलन के कार्यवृत्त.—(1) आयोग के प्रत्येक सम्मिलन के कार्यवृत्त, उसके सम्मिलन के ठीक दौरान या उसके पश्चात् सचिव द्वारा या आयोग के किसी सदस्य द्वारा, जैसा निर्देशित किया जाए, लेखबद्ध किए जाएंगे।

(2) आयोग के सम्मेलन के कार्यवृत्त अनुमोदन के लिए अध्यक्ष को प्रस्तुत किये जाएंगे तथा अनुमोदन होने पर शीघ्र ही तथा किसी भी दशा में आगामी सम्मेलन प्रारंभ होने के पर्याप्त समय पूर्व आयोग के सदस्यों को परिचारित किए जाएंगे.

(3) आयोग द्वारा प्रारंभ किए गए प्रत्येक मामले के निष्कर्षों को किसी राय के रूप में लेखबद्ध किया जाएगा तथा विपरीत राय, यदि दी जाती है, तो वह अभिलेख का भाग होगी तथा वह अभिलेख में रखी जाएगी. जहां राय में कोई भिन्नता होती है वहां बहुमत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

(4) आयोग के समस्त आदेश तथा विनिश्चय सचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से सचिव द्वारा प्राधिकृत किए गए आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जाएंगे.

(5) जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो, आयोग द्वारा सम्मेलन के कार्यवृत्त पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि उसकी पुष्टि अध्यक्ष द्वारा नहीं कर दी जाती.

(6) आयोग के समस्त सम्मेलनों के अभिलेख की मास्टर प्रति तथा सचिव द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित राय रखी जाएगी.

(7) प्रत्येक मदों से संबंधित कार्यवृत्त की एक प्रति समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित फाईलों (नस्ती) में रखी जाएगी. रायों को संबंधित अभिलेखों में रखा जाएगा तथा सुविधा के लिए उसकी प्रतियां समुचित सूचियों के साथ सुरक्षित फाईलों में रखी जाएगी.

17. की गई कार्यवाही की रिपोर्ट.—सचिव द्वारा प्रत्येक परचातवर्ती सम्मेलन में अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट, जिसमें ऐसी मदों को छोड़कर, जिनमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, ऐसी प्रत्येक मद पर, जिनके संबंध में आयोग द्वारा उसके किसी पूर्व सम्मेलन में विनिश्चय किया गया था, की गई कार्यवाही के विद्यमान प्रक्रम को उपदर्शित करते हुए, आयोग को प्रस्तुत की जाएगी.

18. मुख्यालय से बाहर कारबार का संव्यवहार.—आयोग या कुछ सदस्य जब भी अध्यक्ष द्वारा पूर्व में अनुमोदित किया गया हो, मुख्यालय से बाहर किसी स्थान पर कारबार का संव्यवहार कर सकेंगे, परन्तु यदि पक्षकारों को अधिनियम के अधीन किसी जांच के संबंध में सुना जाना हो तो ऐसे प्रयोजन के लिए कम से कम दो सदस्यों से आयोग की खंडपीठ का गठन होगा.

19. परामर्शदाताओं का पैनल.—(1) आयोग, विभिन्न कार्यों जैसे अन्वेषण या जांच, कृतिक बल (टारक फोर्स) या समितियों को सेवा देने हेतु तथा अनुसंधान और विश्लेषण के लिए आयोग की सहायता करने हेतु परामर्शदाताओं का एक पैनल बना सकेगा.

(2) आयोग पैनल बनाने हेतु शैक्षिक, अनुसंधान, प्रशासनिक, अन्वेषणीय, विधिक या सिविल सामाजिक समूहों से विशेषज्ञ ले सकेगा.

(3) आयोग इन परामर्शदाताओं का पैनल बनाने के लिए परदर्शी प्रक्रिया अपना सकेगा. जिससे वे कार्यों के त्वरित प्रत्यागोजन के लिये उपलब्ध हो सकें.

20. वार्षिक रिपोर्ट.—(1) आयोग प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक प्रारंभ होने वाली कालावधि के लिये वार्षिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा.

(2) आयोग, विशिष्ट विवादाओं पर जब कभी अध्यक्ष के निर्देश के अधीन आवश्यक हो, विशेष रिपोर्ट भी तैयार करेगा.

(3) राज्य सरकार, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखवाएगी.

(4) वार्षिक रिपोर्ट में किसी अन्य मामले के जिसे आयोग रिपोर्ट में सम्मिलित करना आवश्यक समझे, अलावा प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर जानकारी, अन्वेषण किए गए/जांच किए गए परिवाद, मामलों पर की गई कार्रवाई, अनुसंधान के व्यय, पुनर्विलोकन, शिक्षा और संवर्धन पर्याय, परामर्श, किसी मामले पर आयोग के व्यय और विनिर्दिष्ट सिफारिशें सम्मिलित होंगी.

(5) उस दशा में जब आयोग यह समझता है कि वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने में समय लग सकता है, तो विशेष रिपोर्ट तैयार कर सकेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकेगा।

(6) सुसंगत वित्तीय वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय पुनरीक्षित बजट प्राक्कलनों के साथ होंगे।

21. वित्तीय अधिकार.—(1) आयोग, अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उसके द्वारा प्राप्त धनराशियों को व्यय करेगा।

(2) आयोग के सचिव को, उन मामलों को छोड़कर जिन पर राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, आयोग को वित्तीय संव्यवहार से संबंधित समस्त शक्तियां होंगी।

(3) सचिव, पदों के सृजन, वेतनमानों का पुनरीक्षण, यानों का उपापन, विधियों के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में पुनर्विनियोग, आयोग के किसी अधिकारी को सेमीनारों, सम्मेलनों या विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अनुज्ञात करने के मामलों में और राज्य सरकार द्वारा, अवधारित ऐसे अन्य मामलों में राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(4) आयोग को मानदेय, यात्रा भत्ता मंहगाई भत्ता से संबंधित निबंधनों और शर्तों पर अग्रिम में सहमत होने पर किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन और विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए किन्हीं व्यक्तियों को परामर्शों या परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त करने की शक्तियां होंगी।

(5) आयोग को सभी वित्तीय शक्तियां, राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए साधारण वित्तीय नियम, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, नियम तथा आर्थिक अनुदेशों द्वारा शासित होंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीवास्तव, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2007

क्र. एफ-10-29-06-पचास-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-29-06-पचास-2, दिनांक 22 दिसम्बर 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीवास्तव, उपसचिव।

Bhopal, the 22nd December 2007

No.F-10-29-06-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 36 of the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 (No. 4 of 2006), the State Government, hereby makes the following rules, namely:—

RULES.

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Commission for Protection of Child Rights Rules, 2007.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 (No. 4 of 2006);

- (b) "Commission" means the Madhya Pradesh State Commission for protection of Child Right constituted under section 17 of the Act;
- (c) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;
- (d) "Member" means the Member of the Commission;
- (e) "Secretary" means the Secretary of the Commission;
- (f) "Section" means the section of the Act;
- (g) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (h) words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. **Selection Committee.**—The Selection Committee referred to in the proviso to Section 18 shall be headed by the Minister-in-charge of the Women and Child Development Department.

4. **Eligibility for appointment as chairperson and other members.**—No person having any past record of violation of human rights or child rights shall be eligible for appointment as Chairperson or other Members of the Commission.

5. **Secretary.**—The State Government shall appoint the Secretary of the Commission under sub-section (1) of Section 21.

6. **Powers and Duties of the Secretary.**—Secretary shall—

- (i) have the powers to execute all decisions taken by the Commission in order to carry out the powers and functions of the Commission as provided in section 13 and 14.
- (ii) exercise and discharge such powers and perform such duties as are required for the proper administration of the affairs of the Commission and its day to day management as specified in section 13 and 14.
- (iii) convene the meetings of the Commission in consultation with its Chairperson and serve notices of the meetings to all concerned.
- (iv) take steps to ensure that the quorum required for convening a meeting of the Commission is secured.
- (v) prepare the agenda of the each meeting of the Commission, and self explanatory notes in consultation with the Chairperson.
- (vi) make available specific records covering the agenda items to the Commission for reference.
- (vii) ensure that the agenda papers are circulated of the members at least two clear working days in advance of the meeting, except in cases when urgent attention is required.
- (viii) prepare the minutes of the meetings of the Commission and shall execute the decisions of the Commission taken in the meeting and shall also ensure placing of the action taken note of the decisions of the Commission before the Commission in its subsequent meetings.
- (ix) Ensure that the procedure of the Commission is followed by it in transaction of its business.

(x) take up all such matters with the Department of Women and Child Development for release of grants, creation of posts, revision of scales, procurement of vehicles, appointment of staff, laying of annual and audit report in State legislature, re-appropriation of funds, residential accommodation, permitting any officer of the Commission for deputation and any other matter requiring the approval of the State Government.

(xi) exercise such financial powers as are delegated to him by the State Government :

Provided that no expenditure on an item exceeding his financial powers shall be incurred without the prior sanction of the State Government.

(xii) be the appointing and disciplinary authority in respect of other officers and employees of the commission.

7. Term of office of Chairperson and Members.—(1) The Chairperson shall, unless removed from his office under section 7 of the Act, hold office for a period not exceeding three years, or till the age of sixty five years, whichever is earlier.

(2) Every Member shall, unless removed from his office under section 7, hold office for a period not exceeding three years, or till the age of sixty years, whichever is earlier.

(3) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1) or sub-rule (2),—

(a) any person who has held the office of Chairperson shall be eligible for re-nomination; and

(b) any person who has held the office of a member shall be eligible for re-nomination as a member or nomination as a Chairperson;

Provided that a person who has held an office of Chairperson or member for two terms, in any capacity shall not be eligible for re-nomination as Chairperson or member, as the case may be.

(4) If the Chairperson is unable to discharge his functions owing to illness or other incapacity, the State Government shall nominate any other Member to act as Chairperson and the Member so nominated shall hold office of Chairperson until the Chairperson resumes office or till the remainder of his term.

(5) The Chairperson or a Member may, by writing under his hand, addressed to the State Government, resign his office at any time.

(6) A vacancy caused by death, resignation or any other reason shall be filled-up by nomination within ninety days from the date of occurrence of such vacancy.

8. Terms and Conditions of service of Chairperson and member.—Terms and condition of service of Chairperson and Members, for which provisions is not made in these rules, shall be such as may be determined by the State Government.

9. Functions of Commission.—The Commission shall perform all or any of the following functions, namely :—

(a) examine and review the safeguards provided by or under any law for the time being in force for the protection of child rights and recommend measures for effective implementation of those safeguards.

(b) present to the State Government, annually and at such other intervals, as the commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards.

- (c) investigate into violation of child rights and recommend initiation of proceedings in such cases.
- (d) examine all factors that inhibit the enjoyment of rights of children affected by terrorism, communal violence, riots, natural disaster, domestic violence, HIV/AIDS, trafficking, maltreatment, torture and exploitation, pornography and prostitution and recommend appropriate remedial measures.
- (e) look into the matter relating to children in need of special care and protection including children in distress, marginalized and disadvantaged children, children in conflict with law, juveniles, children without family/destitute children and children of prisoners and recommend appropriate remedial measures.
- (f) study treaties and other international instruments and undertake periodical review of existing policies, programmes and other activities on child rights and make recommendations for their effective implementation in the best interest of children.
- (g) undertake and promote research in the field of child rights.
- (h) spread child rights literacy among various sections of the society and promote awareness of the safeguards available for protection of these rights through publications, media, seminars and other available sources.
- (i) inspect or cause to be inspected any juvenile custodial home, or any other place of residence or institution meant for children, under the control of the Central Government or State Government or any other authority, including any institution run by a social organization; where children are detained or lodged for the purpose of treatment, reformation or protection and take up with these authorities for remedial action, if found necessary.
- (j) inquire into complaints and take *suo motu* notice of matters relating to—
 - (1) deprivation and violation of child rights,
 - (2) non-implementation of laws providing for protection and development of children,
 - (3) non-compliance of policy decisions, guidelines or instruction aimed at mitigating hardships to and insuring welfare of the children and to provide relief to such children,
 or take up the issues arising out of such matters with appropriate authorities; and
- (k) perform duties as are specified by the State Government relating to any such matter.

10. **Additional functions of Commission.**—The Commission shall, in addition to the functions assigned to it under rule 9, also perform the following functions, namely :—

- (a) analyse existing law, policy and practice to assess compliance with convention on the rights of the child undertake inquiries and produce reports on any aspect of policy or practice affecting children and comment on proposed new legislation from a child rights perspective;
- (b) present to the State Government annually and at such intervals as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;
- (c) undertake formal investigations where concern has been expressed either by children themselves or by concerned person on their behalf;
- (d) ensure that the work of the commission is directly informed by the views of children in order to reflect their priorities and perspectives;

(e) promote, respect and serious consideration of the views of children in its work and in that of all Government Departments and Organizations dealing with child;

(f) produce and disseminate information about child rights;

(g) compile and analyze data on children; and

(h) promote the incorporation of child rights into the school curriculum, teachers training of personnel dealing with children.

11. **Headquarters of State Commission.**—The Head Quarter of the State Commission shall be at Bhopal.

12. **Place of meetings.**—The State Commission shall ordinarily hold meeting in its office located at Bhopal, but may in its discretion hold its meetings at any other place in Madhya Pradesh, if it considers it necessary or expedient to do so.

13. **Periodicals of the meetings.**—The Commission shall meet regularly at its office at Bhopal at such time as the Chairperson thinks fit, but three months shall not intervene between its last meeting and the next meeting. Even though the Chairperson, may direct to call the special meeting of the Commission for considering any necessary specified matter, on the initiative of his/her own or one or more than one Member.

14. **Procedure for the disposal of complaints.**—(1) All complaints, which are received by State Commission in any manner, shall be registered and assigned to them a number and shall be kept before the two member judicial bench constituted for this purpose for admission ordinarily not more than two weeks from the date of its receipt. Ordinarily the complaints of following nature are not admissible for Commission:—

(a) in relation to those incidents occurred before, more than a year from presenting the complaint;

(b) in relation to such matters which are 'sub-Judicial';

(c) which are not clear, without any name or disguised name;

(d) which are insignificant in nature;

(e) which are outside the jurisdiction of Commission.

(2) No fees shall be payable for complaints.

(3) Every complaint should be made in Hindi or English so that Commission shall be able to process quickly and every efforts should be made by which the nature of the matter shall become complete clear, for the reason it is made. Nevertheless for the convenient filing of the complaints, the Commission may accept complaints made in any language included in Eighth Schedule of the Constitution. The Commission whenever thinks necessary, shall have freedom to call upon the filing of affidavits, more information in support of allegations.

(4) The Commission at its discretion shall admit the complaints sent by telegraph or e-mail and the complaints through fax.

(5) The Commission shall have the powers to reject any complaint in limine.

(6) After the admission of a complaint Chairperson/ Commission shall direct whether the matter shall be kept for inquiry or further investigation should be made.

(7) In respect of every complaint on which the Chairperson/Commission have decided that whether it should inquire or investigate, then the Commission shall call the report/comments from the Governments/Authority concerned and for this purpose appropriate time shall be given to the Government/ Authority.

(8) On the receipt of the comments of the authority concerned, a detailed note on that matter on merits shall be prepared for the consideration of the Commission.

(9) **The Commission on suo motu take action.**—The Commission at its discretion may provide opportunity of personal hearing to petitioner or any person on behalf of petitioner and if the Commission is of the opinion that those other person or persons should be heard for the appropriate disposal of the matter before it and in relation to that where it is necessary it may call for records and examine the subjects. The Commission shall provide appropriate opportunity of hearing to those persons whose character has been the subject matter of its inquiry and in its opinion that there is a possibility of adverse effect on their goodwill and give opportunity for cross examination of witnesses, if any, in support of complaint and give opportunity to present their evidence.

(10) Where the investigation has been made by a team of the Commission or any other person, such report shall be presented within a week or such more time, as may be permitted by the Commission, from the date of its completion. In any specific matter, if the Commission is of the opinion that investigation has not been made in a proper way or to ascertain the truth or to enable to dispose of that matter properly further investigation in that matter is required then, the Commission at its discretion may direct for further investigation.

(11) The Commission or when the Chairperson has made such request than any member from amongst the members of Commission may tour for the study at site and where such study is made by one or more Members, then that report shall be given to Commission as soon as possible.

15. Procedure for transaction of business of Commission.—(1) The Secretary of the Commission, along with such officers as the chairperson may direct, shall attend the meetings of the Commission.

(2) The secretary shall, in consultation with the Chairperson, prepare the agenda for each meeting of the Commission and shall have notes prepared for the use of the Commission and such notes shall, as far as possible, be self-explanatory.

(3) The records covering the agenda items shall be made readily available to the Commission for reference.

(4) The agenda papers shall ordinarily be circulated to members at least two clear working days in advance of meeting, except in cases when urgent attention is required.

(5) Four members including the Chairperson shall form the quorum at every meeting of the Commission.

(6) All decisions of the Commission at its meetings shall be taken by majority:

Provided that in the case of equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding shall have and exercise a second or a casting vote.

(7) If, for any reason, the Chairperson is unable to attend the meeting of the Commission, any members chosen by the members present from amongst themselves at the meeting, shall preside.

16. Minutes of meeting.—(1) The minutes of each meeting of the Commission shall be recorded during the meeting itself immediately or thereafter by the Secretary or by any other officer of the Commission as directed.

(2) The minutes of meeting of the Commission shall be submitted to the Chairperson for approval and, upon approval, be circulated to all, members of the Commission at the earliest and in any case sufficiently before the commencement of the next meeting.

(3) The conclusions of the Commission in every matter undertaken by it shall be recorded in the form of an opinion and dissenting opinions, if given, shall also form part of and be kept on record. Action shall be taken on basis of majority opinion where there is any difference of opinion.

(4) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Secretary with the prior approval of the Chairperson in this behalf.

(5) Unless specifically authorized, no action shall be taken by the Commission on the minutes of the meetings until the Chairperson confirms the same.

(6) A master copy of the record of all meetings and opinions of the Commission shall be maintained duly authenticated by the Secretary.

(7) A copy of the minutes pertaining to each item shall be kept in the respective files for appropriate action. Opinions shall be kept in respective records and for convenience, copies thereof with appropriate indexing shall be kept in guard files.

17. Report of action taken.—Report of the follow up action shall be submitted by the Secretary to the Commission at every subsequent meeting indicating therein the present stage of action taken on each item on which the Commission has taken any decision in any of its earlier meetings excepting the items on which no further action is called for.

18. Transaction of business outside headquarters.—The Commission or some Members may transact business at places outside its headquarters as and when previously approved by the Chairperson, provided that if parties are to be heard in connection with any inquiry under the Act, at least two Members shall constitute the Bench of the Commission for such purpose.

19. Panel of consultants.—(1) The Commission may constitute a panel of consultants for assisting the Commission in a wide range of tasks such as investigation or inquiry, to serve on task forces or committees and for research and analysis.

(2) The Commission may draw on experts from academic, research, administrative investigative, legal or civil society groups to form the panel.

(3) The Commission may devise a transparent process for empanelling these consultants so that they are available for quick delegation of tasks.

20. Annual report.—(1) The Commission shall prepare and publish an annual report for the period starting from 1st April to 31st March of the commencing year, every year for submission to the Government.

(2) The Commission shall also prepare special reports of specific issues as and when necessary under the direction of the Chairperson.

(3) The State Government shall cause the annual report and the special reports of the Commission to be laid before the State Assembly.

(4) The annual report shall include information on administrative and financial matters, complaints investigated/inquired into, action taken on cases, details of research, reviews, education and promotion efforts, consultations, details and specific recommendations of the Commission on any matter, besides any other matter that the Commission may consider warranting inclusion in the report.

(5) In case the Commission considers that there could be a time lag for the preparation of the annual report, it may prepare and submit a special report to the State Government.

(6) The estimated receipts and expenditure shall be accompanied by the revised budget estimates for the relevant financial year.

21. Financial powers.—(1) The Commission shall spend the sums of money received by it for the purposes of the Act.

(2) The Secretary of the Commission shall have all powers relating to financial transaction of the Commission, except in cases, which require prior approval of the State Government.

(3) The Secretary shall obtain prior approval of the State Government in matters of creation of posts, revision of pay scales, procurement of vehicles, re-appropriation of funds from one-head to another, permitting any officer of the Commission to participate in seminars, conferences or training programmes abroad and such other matters determined by the State Government, by order.

(4) The Commission shall have powers to engage any persons as consultant or consultants for a specific purpose and for a specific period on the terms and conditions agreed in advance relating to honorarium, traveling allowance, dearness allowance.

(5) All financial powers of the Commission shall be governed by the general financial rules, delegation of financial powers rules and economy instructions issued by the Finance Department of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AKHILESH SHRIVASTAVA, Dy. Secy.